











हाल के दिनों में बांगलादेश के हैंदू मरिंदों में हुए हमलों की भारत द्वारा कड़ी निंदा सरकार की किंवदन्ति विमुहूता की स्थिति को ही दर्शाता है। जीते अगस्त में शुरू हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बीच शेष हसीना का प्रधानमंत्री पद से हटना और भारत आने के बाद बांगलादेश में भारत विरोधी गतिविधियों को असामाजिक तत्वों व कट्टरपक्षियों द्वारा हवा दी गई। जिसमें तमाम स्थानों पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाने पर लिया गया। जिसके बाद नई दिल्ली ने बांगलादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में बार-बार चिंता व्यक्त की है। यह विडंबना ही है कि नेबेल शांति पुरस्कार विजेता व कार्यवाहक रूप में सरकार के मुखिया का दायित्व निभा रहे मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में दिंदू पहचान के प्रतीकों को निशान बनाया जाना बदस्तूर जारी है। इसमें धार्मिक स्थलों और पूजा पंडालों को अपवित्र करने, तोड़फेड़ और डकैती जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं। इस पर यूनुस की दलील रही है कि ये हमले राजनीति से प्रेरित हैं और इन्हें सांप्रदायिक नहीं कहा जा सकता। वहीं बार-बार धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के आश्वासन और समय-समय पर मार्दिंदों में जाने के बाबूजूद बांगलादेश में अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत के एक व्यवस्थित पैटर्न को पनपने दिया जा रहा है। बीच-बीच में सरकारी नौकरियों व शिक्षकों की भूमिका निभा रहे अल्पसंख्यकों को जबरन इस्तीफा देने के लिये दबाव बनाने के अरोप भी लगते रहे हैं। यहाँ तक कि मशहूर जेशेश्वरी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बांगलादेश यात्रा के दौरान दिए गए मुकुट के चोरी हो जाने का समाचार पिछले दिनों आया। निस्सदैह, अल्पसंख्यकों के खिलाफ यह मुहिम गंभीर चिंता का विषय है। निश्चित रूप से, यह भारत-बांगलादेश के संबंधों के लिये परीक्षा का समय है। मुकदमा चलाने के लिये शेष हसीना को वापस भेजने की मांग पर नई दिल्ली की चुप्पी ने ढाका में हलचल बढ़ाई है। दरअसल, बदले हालात में वहाँ एक वर्ग का उद्य हुआ है जो चाहता है कि बांगलादेश अपने शक्तिशाली पड़ोसी से आंख में आंख डालकर बात करे। हालांकि, यह धारणा गलत व अव्यावहारिक है। पिर भी दोनों पक्षों को बढ़ाते अविश्वास की खाई को पाठने में किसी भी देरी को टालना होगा। राजनीतिक चौनलों को पूरी ताकत के साथ सक्रिय करने की जरूरत है। जिसके लिये जरूरत पड़ने पर सख्ती दिखाने की भी जरूरत होगी। ऐसे में पश्चिमी देशों के पोस्टर बॉय बने सत्ता की बागेरे संभालने वाले मोहम्मद यूनुस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर फिलहाल बांगलादेश में जो हो रहा है, वह भारत के लिये भी एक सबक है। अपने देश में भी अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह का भेदभाव व दुराग्रह उतना ही अनुचित होगा, जैसा बांगलादेश में अल्पसंख्यकों के साथ किया जा रहा है। यह भेदभावपूर्ण व्यवहार व बेतुकापन खत्म होना चाहिए। यह भारत की वसुधैव कुटुम्बकम् की नीति के विरुद्ध होगा। दूसरे शब्दों में यह भारत और भारतीयता का अपमान भी होगा। हर देश में अल्पसंख्यकों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार वक्त की पहली जरूरत है।

प्रियकार

**शोध आर नवाचार में भारत का ऊपराई**  
100 विज्ञान एवं प्रैद्योगिकी कलस्टरों में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री मिशन ने भी अहम भूमिका निभाई है। ए

— خانہ ایجاد —

सूचीबद्ध हैं और भारत अमूर्त संपत्ति तीव्रता में वैधिक स्तर पर सातवें स्थान पर है। जीआईआई 2024 के अनुसार, स्ट्रिंजरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूके दुनिया की सबसे अधिक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जबकि चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम और फ़िलीपींस पिछले एक दशक में सबसे तेजी से ऊपर आने वाले देश हैं। यदि हम बौद्धिक सम्पदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े अन्य वैधिक संसाधनों की पर्योर्णी को भी देखें तो पाते हैं कि भारत इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी डिग्रो मंडल यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स' के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी वैधिक बौद्धिक संपदा (आईडी) सूचकांक 2024 में भारत दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है।

निस्पर्दह शोध एवं नवाचार तथा बौद्धिक सम्पद की दुनिया में भारत की ऐसिंग यह दर्शा रही है कि भारत इनोवेशन का हब बनता जा रहा है। भारत में शोध एवं नवाचार को बढ़ाने में डिजिटल ढंगे और डिजिटल सुविधाओं की भी अहम भूमिका है। भारत आईटी सेवा नियंत्रित और वेंचर कैपिटल हासिल करने के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। विज्ञान और इंजीनियरिंग ऐजेंटिट तैयार करने में भी भारत दुनिया में सबसे आगे है। भारत के उद्योग-कारोबार तेजी से समय के साथ आधुनिक हो रहे हैं।

ने कारोबारी विशेषज्ञता, रचनात्मकता, गणनीतिक और संचालन से जुड़ी विशेषता, सरकार की प्रभावशीलता जैसे विविध क्षेत्रों में अच्छे सुधार किए हैं। साथ ही भारत में घेरेलू कारोबार में सलता, विदेशी निवेश जैसे मानकों में भी बड़े सुधार दिखाई दिया है। भारत की शोध एवं नवाचार ऊर्जाएं में अपर ज्ञान पूँजी, स्टार्टअप और यूनिकॉर्प, पेटेंटिंग, बृद्धि, घेरेलू उद्योग विविधकरण, हाईटेक विनिर्माण और सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए प्रभावी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए प्रभावी कार्यों के साथ-साथ अटल इनोवेशन

माहौल के चलते अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने ग्लोबल इन हाउस सेटर (जीआईसी) तेजी से शुरू करते हुए दिखाई दे रही हैं। इसमें कई दो मत नहीं है कि सरकार बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार की अहमियत को समझते हुए इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए दिखाई दे रही है। वर्ष 2024-25 के बजट में वित्तमंत्री सीतासमण ने उभरते क्षेत्रों में नवाचार और शोध को प्रोत्साहन देने के लिए एक लाख करोड़ रुपए के कोष की स्थापना की है। यद्यपि भारत के विकास में बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े तीन आधारों की बढ़ती भूमिका दिखाई दे रही है, लेकिन इन आधारों से विकास को ऊंचाई देने के लिए इस क्षेत्र में सरकार व निजी क्षेत्र का परिव्यय बढ़ाना होगा। इस समय भारत में आरएंडडी पर जीडीपी का करीब 0.67 प्रतिशत ही व्यय हो रहा है। दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब दो फीसदी शोध एवं विकास में व्यय किया जाता है। ऐसे में हमें ध्यान देना होगा कि कोई 6-7 दशक पहले अमेरिका ने आरएंडडी पर तेजी से अधिक खर्च करके सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, दिवाओं, अंतर्रिक्ष अन्वेषण, ऊर्जा और अन्य तमाम क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने का अध्याय लिखा है।

आभासी दुनिया। युवा इस आभासी दुनिया यानी रील पर अधिक लाइक्स के चक्र में खुद को जोखिम में डाल रहे हैं। भारत में टिकटॉक पर बैन लगाने के बाद रील्स और मीस बनाने का चलन समने आया। इसके बाद लोग इंस्टाग्राम पर बीडियो डालने लगे। रील्स में फैमिशनल, फनी, मोटिवेशनल और डांस समेत कई तरह के बीडियो होते हैं। रील्स एक तरह का इंस्टाग्राम पर शॉट बीडियो होता है। शुरुआत में यह रील्स 30 सेकंड का होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 90 सेकंड का कर दिया गया। रील बनाने का युवाओं के बीच ऐसा ऋज आजकल है कि वह कहीं भी रील बनाने लग जाते हैं। कई बार इस रीलबाजी के चक्र में लोग अपना ही नुकसान भी करा बैठते हैं। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ने के शास्त के कारण युवा लाइफ में रील बनाने का ऋज बढ़ता जा रहा है। कब यह शौक सनक की हड तक पहुंच जाता है, पता ही नहीं चलता। नियमों को ताक पर रखकर रील बनाने के जुनून में जान तक गंवा देते हैं। शहरों में ही युवाओं को फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ने के लिए जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक, फ्लाई ओवर पर, चलती रेल में कोच के डिब्बे के बीच खड़े होकर या बाइक चलाते हुए रील बनाते देखा जा सकता है।

कई युवा रील को रोचक बनाने के चक्र में पानी के बीच ऊर रहे हैं तो कई तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने या अपने फॉलोअर्स बढ़ने के जुनून में लोग इतने खो जाते हैं कि कुछ अलग हटकर दिखाने के चक्र में खुद के साथ-साथ कई बार दूसरों तक की जान से खिलबाड़ कर डालते हैं। लोकप्रियता हासिल करने के लिए कभी कोई रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने पहुंच जाता है तो कभी कोई बहुमजिला इमारत पर खड़े होकर बीडियो बनाता है। कभी बाहर चलाते समय स्टटबाजी, कभी सड़कों व चौक-चौराहों पर डांस, स्टंट करना और बांध पर खड़े होकर रील्स बनाना। कभी-किसी पहाड़ पर खड़े होकर अंजीब हरकतें करना। कहीं झस्तों व जलाशयों के बीचोंबीच जाकर पानी में बेपरवाह मस्ती करते हुए रील्स बनाना। कभी रेलवे ट्रैक पर जाकर या प्लेटफर्म या चलती ट्रेन में दरवाजे पर खड़े होकर रील्स बनाना। रील लाइफ की तुलना से युवाओं का आन्तसम्मान प्रभावित हो रहा है। सोशल मीडिया की दुनिया में रफेक्ट दिखने की होड़ में जब उनकी पोस्ट को बाढ़ित प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो वे निश्च हो जाते हैं। इसका साधा असर उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है, जिससे वे और अधिक सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं और इस चक्रवृहू में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस समस्या से निपटने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों को मिलकर युवाओं को बनाने की बजाय मोटिवेशनल, संगीत, नृत्य, तकनीकी ज्ञान, सेहत से जुड़ी इप्स, धर्म, विज्ञान, फिटनेस, हास्य-व्यंग्य, खाना-पान सहित सैकड़ों विषयों पर रील्स बनाकर ख्याति अर्जित की जा सकती है। रील्स देखने के कारण बच्चे वर्चुअल ऑटोइंज के शिकार हो रहे हैं, उन्हें मोबाइल से दूर रखें। बच्चों के सामने कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें। बच्चों के वक्त दें, उनसे पारिवारिक बातें करें। सोशल मीडिया के चलते बच्चों और युवाओं में सामाजिक दिखावे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। युवा फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक-टूसरे की देखाएंदखी बातें कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता होता कि इसकी नतीजा क्या होगा। उन्हें वास्तविकता का पता नहीं है। बच्चे अपने माता-पिता की बात नहीं मानते हैं। जो उम्र पढ़ें की होती है उसमें रील बना रहे हैं। रिस्क भी ज्यादा लेते हैं। ऐसे बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों की भी काउंसिलिंग की जरूरत है। युवाओं के साथ-साथ अब छोटे बच्चों में भी मोबाइल पर रील्स बनाने की आदत होने लाई है। बच्चे घर पर अकेले रहते हैं। सोशल मीडिया का अटैक्शन है सबको अच्छा लगता है कि उन्हें लोगों परसंकर, तारीफ करें। इससे बचने का यही उपाय है कि बच्चों को मोबाइल फोन का प्रयोग कम करने दे। मोबाइल देखते समय बड़े उनके साथ ही रहें। जिससे वह कुछ गलत न कर सके।



# રાષ્ટ્રપતિ

**मेष:-** परिवार की छोटी-छोटी बातों  
बाहरी लोगों से न कहें। भावना से  
उद्भेदित मन संबंधियों के सुख-दुख के प्रति  
चिंतित होगा। किसी नई दिशा में सकारात्मक  
सोच अवश्य रंग लायेगी।

**वृथाथः-** हर घटना से आपको सीख लैने की जरूरत है। नये क्षेत्र में निवेश से पूर्व जानकार लोगों से विचार-विमर्श करें। भविष्य के प्रति निराशाजनक विचारों को

**मन पर हावी न होने दें।**

**मिथुन:-** निकट संबंधों में मधुर संवाद से अपनी सुंदर छवि बनायें। कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति होने के आसार हैं। सामान्य दिनचर्या के साथ बीत रहे

**जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा।**

**कर्क:-** भविष्य संबंधी कुछ चिंताएँ उत्पन्न होंगी। किसी कार्य को छोटा-बड़ा समझने के बजाए अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करें। वर्तमान कार्य से मन

**असंतुष्ट रहेगा।**

**सिंह:-** परिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए चिंता उत्पन्न होगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापत्वाही न बरतें एवं जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दें।

**कन्या:-** कोई छोटी बात भी परिवार में तनाव का कारण बन सकती है। महत्वपूर्ण प्रयत्न की सार्थकता हेतु नये उत्साह का संचार होगा। सामाजिक गतिविधियों में क्रियाशीलता बढ़ेगी। भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंध मधुरत होंगे।

पुराणा वृत्ति अनुसार

**सा** नन पाण्युक क नृप म एक  
महीने से ज्यादा समय से लदार  
से अपनी मांगों को लेकर  
पाठ्यावा करते दा 100 ग्रे अधिक लोग

पदयात्रा करत हुए 100 से आधक लाग  
दिल्ली पहुंचे। कठिन जलवायु में इतनी लंबी  
यात्रा करके 80 वर्ष के बूढ़े साथियों समेत  
ऐसे दल दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचा क्या दलवें

य दल दिला पुड़चा। दिला पुलिस का इन साथ व्यवहार कुछ अच्छा नहीं रहा। यह लोग शाति पूर्ण ढंग से अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। दिली पुलिस इन्हें शक की नजर से देख रही है। अभी तक सरकार से आंदोलनकारियों को बातचीत

के लिए कोई संदेश नहीं मिला। हरियाणा  
और जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव के चलते  
सरकार की अति व्यस्तता तो समझ में  
आती है किन्तु अब कोई बाधा नहीं दिखती।  
इसलिए यह आशा की जानी चाहिए कि  
प्राकृति अपनी सभी बार्ताएँ करके ऐसा

सरकार आतं शांघ वाना करकं सोनम  
 वांगचुकं का आमरण अनशन समाप्त  
 कराएगी। इससे समस्या का सर्व समावेश  
 हल तलाश करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त  
 होगा।  
 सोनम वांगचुक पिछली सर्दियों में भी

लद्धाख की कुछ मार्गों का लेकर लंबा अनशन कर चुके हैं। उनकी कुछ मार्गों केवल लद्धाख केन्द्रित हैं और कुछ पूरे हिमालय के संवेदनशील पर्यावरण को बचाने से संबंधित हैं। लद्धाख को सी श्रेणी राज्य का दर्जा दे कर विधानसभा और उपराज्यपाल की व्यवस्था की जा सकती है। जाहिर है कि स्थानीय समस्याओं को जितना चुने हूँ प्रतिनिधि समझ सकते हैं,



# ਲਾਈ ਆਦਾਲਨ ਕਾ ਅਨਦੰਖਾ ਜਾਂਹਾ

उतना प्रश्नासनिक तत्र नहीं समझ सकता, जिससे लोगों में असतोष बना रह सकता है। इस रीमान क्षेत्र में देश किसी असतोष को सहन करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी मांग छठी अनुसूची में डालने की है। भारतीय सविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार छठी अनुसूची लागू की गई। छठी अनुसूची को स्वायत्र जिला परिषदों की स्थापना और संचालन करके खदेशी आदिवासी समूहों की रक्षा के लिए बनाया गया था। असम, मिजोरम, और मेघालय में भी इसी तीन-तीन स्वायत्र जिला परिषद हैं, जिपुरा में केवल एक है। स्वायत्र जिला परिषदों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें भूमि, खेती, विरासत, वन, और वन्यजीवी-रिति- रिवाजों सहित आदिवासी और खदेशी समूहों से संबंधित हर पहलू को शामिल किया गया है। उन्हें भूमि और अन्य कर एकत्रित करने का भी अधिकार है। इससे छठे अनुसूची क्षेत्रों को बाहरी दबाव से बचाव की प्रभावी शक्तियां मिल जाती जिनका उपयोग स्थानीय संघेदनशील पर्यावरण और परंपराओं को संरक्षित करने किया जा सकता है। पर्वतीय लोग आर्थिक रूप से उतने सशक्त नहीं होते वर्योंकि वहाँ संसाधनों की कमी रहती है, यदि कुछ संरक्षण न दिया जाए तो पैसे वाले लोग वहाँ के संसाधनों को खरीद कर स्थानीय लोगों को हाशिए पर ला सकते हैं। यह डर सभी पर्वतीय राज्यों में कमोबेश रहा है। आदिवासी लोगों में यह और भी ज्यादा है। इस मुद्दे पर चर्चा करना रास्ता निकला जा सकता है, लेकिन उन्हें वित्त निराधार नहीं ठहराई जा सकती। सुना गया है कि लदाख के लोगों से छठे अनुसूची में लाने का बाद वर्मान सरकार द्वारा किया गया था। तब तो इस समस्या

चाहिए। फिर भी सरकार हिचकिचा कर्यो रही है समझ से परे है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों के बारे में उनकी मांगें हिमालयी प्रदेशों के लिए महत्व रखती हैं। इसी कारण अन्य हिमालयी राज्यों में भी सोनम वांगचुक के संघर्ष के प्रति समर्थन का भाव है। पर्यावरण मित्र विकास और बृहदाकार निर्माण आधारित विकास में टकराव पूरे हिमालय में ही देखने को मिल रहा है। बृहदाकार निर्माण आधारित विकास संवेदनशील हिमालयी परिस्थिति तत्र को तोड़फोड़ कर आगे बढ़ता है जिससे एक ओर पर्वतीय क्षेत्रों में मानव निर्मित आपदाओं में बढ़तीर हो रही है तो दूसरी ओर लोगों को पर्याप्त रोजगार भी नहीं मिल रहा। आपदाग्रस्त और विस्थापितों का पुनर्वास भी ढड़ी समस्या बना हुआ है। भाखड़ा और पोंग बांधों के विस्थापित अभी तक भी पूरी तरह से बस नहीं पाए हैं। इसलिए हिमालय में विकास के लिए वैकल्पिक मॉडल की खोज नवाचार के माध्यम से करनी होगी। कम से कम इन्हाँ तो मान कर ही चलना होगा कि हिमालय के लिए स्माल इज ब्यूटीफुल पर्वतीय राज्यों पर जलविद्युत उत्पादन का बड़ा दबाव है। इसमें कुछ नदियों तो लुप्तप्रायः ही हो गई हैं। ये झील में हैं या सुरंग में हैं। नदी तंत्र की रक्षा के लिए नदी दोहन की कोई सीमा निर्धारित करनी होगी। मान लो 60 फीसद से ज्यादा नदी का दोहन नहीं करेंगे, तो नदी भी जिंदा रहेगी और बिजली भी बन जाएगी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नदी तंत्र पर जलविद्युत

**स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक:** जितेन्द्र सिंह द्वारा एवीबी रिप्रोग्राफिक्स ए-59 इण्डस्ट्रियल एरिया तालकटोरा लखनऊ से मुद्रित एवं कार्यालय 2/353, विशाल खण्ड-2 गोमती नगर लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक जितेन्द्र सिंह\*  
 (\*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के तहत उत्तरदायी\*) समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही मान्य होंगे। आरएनआई न . UPHIN/2013/55887











विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न देशों से अपील करते हुए कहा

# भारत की प्रतिभाओं का लाभ ले दुनिया

एजेंसी

नवी दिल्ली | विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न देशों से आज अपील किया कि वे भारत की प्रतिभाओं एवं युवा जनशक्ति का अपने यहां विकास के लिए लाभ लें।

डॉ जयशंकर ने यहां सुप्रभात स्वराज भवन में प्रवासी श्रमिकों के कानूनों एवं सुरक्षित प्रवासन के लिए विदेशी रेजिस्टर के रोजगार प्रभाग द्वारा विकसित पोर्टल 'ईमाइट्रेट' के नये संस्करण के